सान्ध्य हिन्दी दैनिक जौनपुर से प्रकाशित

# देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 127 | जौनपुर, शुक्रवार 02 फरवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

## संक्षिप्त खबरें

### हेमंत सोरेन ने दिया इस्तीफा, चंपई होंगे झारखंड के नए सीएम

रांची, एजेंसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। वे खुद शाम करीब सवा आठ बजे इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंचे। सत्तारूढ़ गठबंधन ने चंपई सोरेन को नया नेता चुन लिया है। चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की मांग लेकर गठबंधन के विधायक राजभवन पहुंचे हैं। इसके पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को सूचित कर दिया कि वह उन्हें गिरफ्तार कर रही है। बताया जा रहा है कि सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। सोरेन को गिरफ्तार किए जाने के संकेत शाम करीब पांच बजे ही मिल गए थे। इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने नए नेता की अगुवाई में सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी थी। गठबंधन के तमाम विधायक बुधवार सुबह से सीएम हाउस में जमा थे। मंगलवार को सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय कर लिया गया था कि उनकी गिरफ्तारी की नौबत आने पर नए नेता की अगुवाई में सरकार के लिए दावा पेश किया जाएगा। राजभवन ने रात 9 से 9.30 बजे के बीच मुलाकात का वक्त दिया है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास से सोमवार को 36 लाख रुपए कैश, एक बीएमडब्ल्यू कार और कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी ने उनसे इसके बारे में कई सवाल पूछे।

### राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 फरवरी को ओडिशा में प्रवेश करेगी

भुवनेश्वर, एजेंसी। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष शरत पटनायक ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 6 फरवरी को राज्य में पहुंचने की संभावना है। शरत पटनायक ने कहा कि सुंदरगढ़ के बीरमित्रपुर में पार्टी नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी का 6 फरवरी की रात को सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। राउरकेला में राजगांगपुर से उत्तरा के बड़गांव होते हुए सुंदरगढ़ तक राहुल गांधी का रोड शो आयोजित किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी झारसुगुड़ा पहुंचेंगे, जहां 7 फरवरी को उनके रात गुजारने की संभावना है। अगली सुबह यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले ब्रजराजनगर, बेल पहाड़, कनकटरा पहुंचेगी। हम 6 फरवरी की रात को बीरमित्रपुर में उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। शरत पटनायक ने मीडिया कर्मियों को यह भी बताया कि राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी ओडिशा के राउर केला, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा सहित तीन संगठनात्मक जिलों को कवर करेगी। पार्टी नेताओं के इसी तरह के कार्यक्रम राज्य के विभिन्न हिस्सों में होंगे।

## लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अमित शाह, जे पी नड्डा भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी लोकसभा चुनाव की प्रत्याशा में, केंद्रीय भाजपा नेताओं ने त्रिपुरा भाजपा नेताओं को नई दिल्ली बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 और 18 फरवरी को चुनावी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा के सूत्रों ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के दृष्टिकोण को आकार देने में सभा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बैठक की पुष्टि की है। उम्मीद है कि राज्य के नेता आगामी चुनावी लड़ाई में एक मजबूत और एकजुट मोर्चा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रणनीतियों, अभियान योजनाओं और समन्वय प्रयासों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में आती है। जैसे–जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टी का लक्ष्य अपने प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और सफल चुनावी अभियान के लिए समर्थन जुटाना है। बैठक में अब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य और बीजेपी महासचिव अमित रक्षित शामिल होंगे। सूत्र ने आगे बताया कि बैठक के दौरान, पार्टी पिछले कुछ वर्षों में राज्य में पार्टी की गतिविधियों पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेगी, जिसमें सदस्यता वृद्धि, तैयारी और चुनाव की योजना का विवरण दिया जाएगा। हम इस राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन तैयारी जरूरी है।

## कांग्रेस के साथ तृणमूल के रिश्ते खराब करने के लिए माकपा जिम्मेदार - मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मार्क्‌ध्सवादी कम्ध्युनिस्ध्ट पार्टी को कांग्रेस के साथ उनकी तृणमूल कांग्रेस के ष्सौहार्दपूर्णष रिश्ते में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मालदा जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ष्मैं एक समय कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस नेतृत्व के साथ मेरी समझ काफी सौहार्दपूर्ण थी। लेकिन सीपीआई–एम के कारण कांग्रेस के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए। ममता ने सीट–बंटवारे की व्यवस्था असफल होने के लिए एक बार फिर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसके नेताओं के एक वर्ग की अत्यधिक मांगों ने अंततः उन्हें पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ष्मैंने बड़े राष्ट्रीय हित के लिए एक साथ काम करने के बारे में सोचा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। उनके पास राज्य से सिर्फ दो लोकसभा सीटें हैं। इसलिए मैं दो सीटों की पेशकश करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब मैंने सोचा कि यह बहुत हो गया। मैं सीपीआई–एम के साथ नहीं चल पाऊंगी, जिसने मुझे बार–बार मारने की साजिश रची। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कई लोगों को मार डाला है। ममता ने यह भी कहा कि माकपा के साथ कांग्रेस के समझौते से वास्तव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा, इसलिए बेहतर है कि तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और भाजपा को हराने के लिए हरसंभव प्रयास करे। बुधवार सुबह न्याय यात्रा रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाहन की पिछली विंडस्क्रीन टूटने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना वास्तव में उनके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से ठीक पहले बिहार में हुई थी। उन्होंने कहा, मैं इस तरह के कृत्यों का समर्थन नहीं करती।

## वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। 6 बार बजट पेश करने के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बराबरी कर ली। उन्होंने भी छह बार बजट पेश किया था। सदन के कार्यवाही शुरू होते ही निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ना शुरू किया। इसके बाद आखिर में वित्त मंत्री ने बजट को सदन के पटल पर रखा और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थीं, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित सभी केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस साल आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया और 56 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त किया जो उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। फिरोजी रंग की कढ़ाई वाली कांथा सिल्क की साड़ी पहनकर संसद पहुंचीं सीतारमण के भाषण के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य उनकी घोषणाओं और टिप्पणियों पर बीच–बीच में मेजें थपथपाते देखे गए। जब उन्होंने कहा कि ''हमारी सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी'' तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सबसे ज्यादा देर तक मेजें थपथपाईं। विपक्षी सदस्यों ने भी वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरे ध्यान से सुना। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार के सत्ता में लौटने संबंधी कथन पर विपक्ष की ओर से कुछ विरोध के स्वर सुनाई दिए। इससे पहले आज पूर्वाह्न 11 बजे बजट भाषण शुरू होने से पहले जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने 'भारत माता की जय', 'जय श्रीराम' और 'जय सियाराम' के नारे लगाए। सीतारमण का 56 मिनट का आज का बजट भाषण उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। सदन में सबसे लंबा बजट भाषण देने का श्रेय भी सीतारमण को जाता है जब उन्होंने साल 2020 में दो घंटे 40 मिनट तक भाषण पढ़ा था।

## विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा अंतरिम बजट – मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट में नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप दिखाया गया है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में शविकसित भारतश का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक–कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद! आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में मा. केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा आज प्रस्तुत अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और श्नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि ये मोदी सरकार का विदाई बजट है।

## अंतरिम बजट सर्व हितैषी – सीएम मोहन यादव

भोपाल, एजेंसी। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इस बजट को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का हितैषी बजट बताया है। अंतरिम बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। लेखानुदान के रूप में प्रस्तुत किया गया आज का बजट सर्वहितैषी और सर्वस्पर्शी है। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। देश में जारी विकास और जनकल्याण के कार्यों से 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आयी है, जो बड़ी उपलब्धि है। भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुआ है। देश में दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जो कल्पना की गई है, वह अद्‌भुत है। मध्यम वर्ग के लिए लाई गई नयी आवास योजना भी उपलब्धिपरक है। बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान योजना का लाभ देने की व्यवस्था की गई है।

## यह बजट मजबूत भविष्य की गारंटी - प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत को समर्पित है। यह अंतरिम बजट विकास का समावेश है। इसमें निरंतरता का भरोसा है, यह विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों– युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा– हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गांवों और शहरों में गरीबों के लिए हमने चार करोड़ से अधिक घर बनाए और अब हमने दो करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा– जिस इनकम टैक्स की नई स्कीम की घोषणा की गई, उससे मध्यम वर्ग के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। पशुओं के लिए नई योजनाएं, पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान से किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी एलान किया गया है। इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।

## प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर समयबद्ध एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी - डीजीपी प्रशांत कुमार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. प्रशांत कुमार द्वारा आज दिनांक 01.02.2024 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में प्रेस वार्ता के दौरान अपने उद्‌बोधन में कहा गया कि– वर्ष 1861 में व्यवस्थापित पुलिस की गौरवशाली परम्परा में वर्ष 1952 में पुलिस कलर प्राप्त हुआ तथा विश्व के विशालतम पुलिस बल का नेतृत्व आई०जी०पी० /डी०जी०पी० रैंक के अधिकारियों द्वारा किया गया। उसी गौरवशाली परम्परा के ध्वज वाहक के रूप में मुझे डी०जी०पी० यू०पी० बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिये मा० मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस देश का विशालतम पुलिस बल है, जिसमें वर्तमान में 03 लाख 13 हजार 946 कर्मचारी कार्यरत हैं। मा० मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुलिस बल को और बेहतर, सक्षम एवं मजबूत बनाने के लिये विगत एक वर्ष में निष्पक्ष एवं पारदर्शी पुलिस भर्ती प्रकिया द्वारा 1,092 आरक्षी एवं समकक्ष, 9,114 उपनिरीक्षक एवं समकक्ष, 1,183 लिपिक वर्ग की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं कुशलता के साथ की गयी। वर्तमान में लगभग 79,082 हजार विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।

मा० मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन–शक्ति अभियान के अन्तर्गत् एण्टी रोमियो स्क्वॉड को और सक्रिय किया जायेगा तथा थाने पर महिला बीट अधिकारी की नियुक्ति तथा महिला साइबर हेल्पडेस्कश एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में पी०ए०सी० महिला पुलिस बटालियनों के व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत् उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश को अपराध मुक्त करते हुये एक सुरक्षित एवं समृद्ध प्रदेश का निर्माण किया है। प्रदेश में अपराधों के शत–प्रतिशत पंजीकरण एवं अपराधों पर प्रभावी नियत्रंण से जनमानस में सुरक्षा की भावना में हुयी बढ़ोत्तरी के साथ–साथ पुलिस की छवि मित्र पुलिस के रूप में स्थापित हुयी है। मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माफिया/अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। एनसीआरवी द्वारा वर्ष 2023 में जारी डाटा के अनुसार यदि अपराध दर की स्थित देखे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत वर्ष का लगभग 16.99 प्रतिशत है तथा आई०पी०सी० के अपराध में सारे राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशो के सापेक्ष आई०पी०सी० में उत्तर प्रदेश का 20वां स्थान है, ऐसे उन्नीस राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश है जिनमें आई०पी०सी० का अपराध दर हमसेअधिक है, इसी प्रकार हत्या में 28वां स्थान, फिरौती हेतु अपहरण में 30वां, दुस्कर्म में 24वां, लूट में 27वां स्थान है, महिला सम्बन्धी अपराध में 14वां स्थान है जबकि महिला सम्बन्धी अपराध में दोषसिद्धि की राष्ट्रीय दर 25.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की दर 70.8 है एवं दोष सिद्धि में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।

मा० मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में अपराधियों को कम से कम समय में सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी कन्विक्शन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत् जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी व उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक तथा अभियोजन विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलायी जा रही है। आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अब तक मा० न्यायालय द्वारा विभिन्न अपराधों में कुल 24,743 अभियुक्तों को दण्डित किया गया है।

मा० मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप जनता की समस्याओं का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण व प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु तैयार किये गये Public Grievance Review Portal प्राप्त होने वाले मैन्युअली प्राप्त प्रार्थना पत्रों को डिजिटाइज्ड (क्पहपजप्रमक) कर, प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर समयबद्ध एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार UP Police नाम से मुख्यालय एवं प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट ध् जनपद स्तर पर व्हाट्सएप चौनल लान्च किया गया है। जिससे जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराया जायेगा।

व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचरष के माध्यम से पुलिस मुख्यालय स्तर से जारी होने वाले निर्देशों जनपदीय पुलिस के सराहनीय कार्यो तथा भ्रामक खबरों के खंडन को प्रदेश के प्रत्येक पुलिस कर्मी तक पहुंचाने हेतु व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर प्रारम्भ किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रचलित है।

# संपादकीय

## बजट का स्वरूप

नाम में क्या रखा है? क्या अंतरिम बजट, जैसा कि आज पेश किया जा रहा है, लेखानुदान के समान है, जैसा कि कुछ टिप्पणीकार, जिन्हें बेहतर पता होना चाहिए, सुझाव दे रहे हैं? स्पष्टता के लिए, हमें यह देखना होगा कि ये शर्तें कहां से आती हैं। लेखानुदान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 116 में स्पष्ट रूप से किया गया है। समेकित निधि से व्यय के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है (अनुच्छेद 113, 114)। जब यह संभव नहीं है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 116 अस्थायी राहत प्रदान करता है। आखघ्रिकार, सरकार काम करना बंद नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इस प्रावधान का उपयोग तब किया जाता है जब चुनाव बुलाए गए हों और मौजूदा सरकार कार्यवाहक हो। इस विशेष मामले में, हम जानते हैं कि चुनाव होंगे, लेकिन वास्तव में अभी तक कोई चुनाव नहीं बुलाया गया है। इसलिए, अभिव्यक्ति 'लेखानुदान' एक मिथ्या नाम है दृ स्वाभाविक रूप से, इसमें करों और व्यय में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके विपरीत, अंतरिम बजट की अभिव्यक्ति संविधान में शामिल नहीं है, जैसे उप प्रधान मंत्री नहीं करते। चुनाव नतीजे आने से पहले वित्त विधेयक पारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इसके अलावा, यह उचित है कि नई सरकार न केवल 2024–25 के लिए, बल्कि 2024–29 के लिए एक रूपरेखा के रूप में अपने कराधान और व्यय प्रस्तावों पर निर्णय लेती है। दूसरे शब्दों में, अंतरिम बजट में करों और व्यय प्रस्तावों में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य इतना बड़ा होना नहीं है। 2024 के लिए निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट पहले ही विच्छेदित हो चुका है। चूंकि मई 2024 में नई सरकार की राजनीतिक संरचना वर्तमान सरकार के समान होने की संभावना है, इसलिए किसी को 2024–25 के पूर्ण बजट का इंतजार करना पड़ सकता है। परंपरागत रूप से, केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा रहा है। (यह राज्य के बजट और संबंधित सर्वेक्षणों के लिए भी उतना ही सच है।) आर्थिक सर्वेक्षण कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। मैं 1950–51 के लिए जॉन मथाई के बजट भाषण को उद्धृत करना चाहता हूंरू "इस स्तर पर मैं जो करने का प्रस्ताव करता हूं वह माननीय सदस्यों को बजटीय स्थिति और बजट की सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि की एक विस्तृत रूपरेखा देना है। यह बजट नए संविधान के तहत पेश किया जा रहा है। इसके मुताबिक, बजट भाषण में अर्थव्यवस्था की लंबी समीक्षा की गई। यह 1958–59 तक इसी प्रकार चलता रहा। वह पहला वर्ष था जब हमने एक अलग आर्थिक सर्वेक्षण बजट से अलग किया था, लेकिन समानांतर रूप से प्रस्तुत किया गया था। बजट भाषण में स्वाभाविक रूप से अभी भी आर्थिक विकास का संदर्भ है, लेकिन सर्वेक्षण में बहुत अधिक विवरण है। पिछले कुछ वर्षों में, सर्वेक्षण के आकार और कवरेज में विस्तार हुआ है। इसे बजट से दो दिन पहले पेश किया जाता है क्योंकि बजट से एक दिन पहले रेल बजट होता था. सर्वेक्षण किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? याद रखें, 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत, बजट के साथ कई अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं दृ व्यापक आर्थिक रूपरेखा विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण। लेकिन ये कभी भी उस तरह का ध्यान आकर्षित नहीं करते जैसा सर्वेक्षण करता है, शायद इसलिए क्योंकि इन दस्तावेजों पर बजट का ग्रहण लग जाता हैय अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेक्षण सीधे तौर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) और उनके कार्यालय के व्यक्तित्व से जुड़ा है। यदि आप सीईए की सूची पर जाएं, तो परंपरागत रूप से, जब तक वे उस पद पर थे तब तक वे कम प्रोफाइल वाले थे। विक्टोरियन कहावत थी कि बच्चों को देखा जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। संदर्भ के अनुरूप परिवर्तन करते हुए, सीईए को (सरकार के भीतर) सुना जाना चाहिए, लेकिन अन्यथा देखा या सुना नहीं जाना चाहिए। कहीं न कहीं, मीडिया में विस्फोट हुआ और सीईए अधिक दृश्यमान हो गए। अक्सर इसका असर आर्थिक सर्वेक्षण के स्वरूप पर पड़ता था. सर्वेक्षण सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित करता है दृ यदि आप चाहें तो वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों के विभाग दृ किसी व्यक्ति के नहीं। ऐसा होने पर, मुख्य मुद्दों के एक निश्चित समूह को कवर करने की आवश्यकता है, जो मौजूदा सीईए की सनक और इच्छा के अधीन नहीं है। हाल के कुछ सीईए ने उस प्रस्ताव पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया है और खुद का प्रचुर हवाला देते हुए सर्वेक्षण को व्यक्तिगत–निर्भर बना दिया है। विश्लेषणात्मक कठोरता के प्रयोजनों के लिए उद्धरण ठीक हैं, लेकिन तब नहीं जब कोई सीईए स्वयं को उद्धृत करने के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता हो। कई साल पहले, जब मैंने अपना पेशेवर करियर शुरू किया था, तो सर्वेक्षण डिजिटल नहीं, बल्कि भौतिक हुआ करता था। और उसे पकड़ने की कोशिश करने की होड़ मच गई। (समाचार पत्र आमतौर पर केवल पहला अध्याय ही छापते हैं।) आर्थिक सर्वेक्षण प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है। यह एक द्वितीयक स्रोत है, जिसका प्राथमिक स्रोत सरकार के भीतर कहीं और है। लेकिन सरकार से बाहर के लोगों के लिए सर्वेक्षण एक प्राथमिक स्रोत था। समय बदल गया है और सर्वेक्षण से स्वतंत्र बहुत सारे डेटा सामने आ रहे हैं, जिनमें डैशबोर्ड और सरकार से प्राप्त अन्य सामग्री भी शामिल है। सर्वेक्षण के औचित्य के रूप में डेटा तर्क अब उतना ठोस नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था।

# भारतीय वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं के बहिष्कार का अभियान

आदित्य

आईसीसी विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को हराने के बाद बांग्लादेश में जश्न के वीडियो पर मिलने वाली गुस्से वाली प्रतिक्रियाओं की तुलना में, हमारे पूर्वी पड़ोसी में हाल ही में शुरू किए गए 'बॉयकॉट इंडिया' अभियान पर प्रतिक्रियाएं मौन रही हैं। मुख्यधारा के मीडिया ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है, हालांकि कुछ यूट्यूब चौनलों ने इस पर टिप्पणी की है। यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत हैं कि भारतीय वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं के बहिष्कार का अभियान यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मुट्ठी भर प्रवासी बांग्लादेशी YouTubers द्वारा चलाया जा रहा है। उनके कुछ हद तक उन्मादपूर्ण व्यंग्य अभी तक बांग्लादेश के मुख्यधारा मीडिया में प्रतिबिंबित नहीं हुए हैं, लेकिन यह बदल सकता है। 1971 में देश की स्थापना के बाद से भारत विरोधी भावना बांग्लादेशी राजनीतिक परिदृश्य की एक विशेषता रही है। मुक्ति का उत्साह कम होने से पहले ही, भारतीय सेना पर नवगठित देश की बची हुई बहुमूल्य संपत्तियों को छीनने के आरोप लगाए गए थे। इसके पीछे पाकिस्तानी उद्योगपति और सेना दोनों हैं। जातीय समाजतांत्रिक दल का गठन, जिसने नवंबर 1975 के तख्तापलट और जवाबी तख्तापलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके संस्थापक मेजर एम.ए. जलील की भारतीय सेना के प्रति घृणा के कारण था। जेएसडी का निर्माण उन भावनाओं पर हुआ जो मौलाना ए.एच.के. की विशेषता थी। भशानी की चीन समर्थक राजनीति। हालाँकि, मुख्य रूप से, 1971 के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएँ दो मुख्य स्रोतों से उत्पन्न हुईं। सबसे पहले, एक मजबूत मुस्लिम पहचान के प्रति वफादारी का भंडार था जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के साथ गायब नहीं हुआ था। मुक्ति संग्राम के आसपास की पौराणिक कथाओं ने बंगाली बोलने वालों के बीच पाकिस्तान समर्थक तत्वों को एक छोटे अल्पसंख्यक के रूप में प्रस्तुत किया, जो मुख्य रूप से जमात से जुड़े थे। –ए–इस्लामी, निजाम–ए–इस्लाम और मुस्लिम लीग के गुट। उनमें से कई ने मुक्ति संग्राम के दौरान सहयोगी के रूप में काम किया और बाद में उन्हें भयानक आरोपों का सामना करना पड़ा। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम धार्मिक दलों को हमेशा कम से कम 25: मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ है। अपने नियंत्रण में एक बड़े कैडर बेस के साथ, उन्होंने हमेशा भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, कम से कम स्थानीय हिंदू आबादी को निशाना बनाकर नहीं। दूसरे, धार्मिक दलों को हमेशा बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की धारा से पूरक किया गया है जो 1975 के बाद जनरल जियाउर रहमान के आसपास एकजुट हो गया था। उन धार्मिक दलों के विपरीत, जिन्हें मुक्ति युद्ध के दौरान उनके पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए कलंकित किया गया था, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने जनरल जिया के पूरक का काम किया है। 1971 में बांग्लादेश की इस्लामी नींव में दृढ़ विश्वास के साथ भूमिका। यह रुख बीएनपी को अवामी लीग से जुड़े 'धर्मनिरपेक्ष' बंगाली राष्ट्रवाद से अलग करने की आवश्यकता के कारण आवश्यक था। अवामी लीग ने हमेशा बीएनपी को मुक्ति–विरोधी ताकतों में शामिल माना है, जिसका मुख्य कारण जिया द्वारा पूर्व पाकिस्तान समर्थक नेताओं का पुनर्वास और उसके बाद खालिदा जिया द्वारा जमात के साथ बनाया गया चुनावी गठबंधन है। अनुमानतः, इन परस्पर विरोधी परंपराओं ने बांग्लादेश में भारत के बारे में जिस तरह से धारणा बनाई गई है।

# देश की सुरक्षा और सीमा निगरानी के लिए ड्रोन की अपरिहार्यता

ललित

आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक तनाव, संघर्ष और युद्ध में ड्रोन का अत्यधिक महत्व है। अक्सर खबरों में देखा जाता है कि रूस–यूक्रेन के युद्ध, मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति और अनेक देशों द्वारा सीमा पर निगरानी और युद्ध के दौरान शत्रु के क्षेत्र में हमलों के लिए ड्रोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन का अर्थ मुख्य रूप से एक रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर द्वारा निर्देशित मानवरहित उपकरण है। इनका उपयोग रक्षा, निगरानी और आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, भू–स्थानिक मानचित्र, खनन, हवाई फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी आदि क्षेत्रों में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। भारत ने शुरुआत में सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध दौरान किया था जहां इजरायल ने भारत को आईएआई हेरॉन और सर्चर ड्रोन दिये थे। तब से आज तक भारत ने इजराइल, अमेरिका आदि से कई सैन्य मानव रहित उपकरण एवं ड्रोन खरीदें हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना घरेलू मानवरहित हवाई वाहन भी विकसित किया है। अभी हाल में ही सोमालिया के पास एमवी लीला समुद्री जहाज के हाइजैकिंग में भारतीय नौसेना ने आनन फानन में एक ऑपरेशन में MQ-9B ड्रोन को तैनात किया और 15 भारतीय चालक दल को बचाया। जून 2021 में जम्मू में भारतीय वायुसेना के एक स्टेशन पर हमले के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। जिसका भारत ने प्रभावी तरीके से जवाब दिया था। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सीमा निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। भारत और चीन के बीच तनाव के दौरान भी ड्रोन के इस्तेमाल ने आर्मी को सतर्क किया था। ड्रोन के माध्यम से स्थितिजन्य निगरानी की जा सकती है और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के आस–पास के समुद्र क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा कार्यों के लिए भी ड्रोन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। ड्रोन समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने, शिपिंग लेन की सुरक्षा और तस्करी, डकैती जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करता है। 2020–21 में भारत ने कोविड महामारी के दौरान न केवल पूरे भारत में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में शीघ्रातिशीघ्र वैक्सीन और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में, बल्कि निकटवर्ती देशों की सहायता, जैसे नेपाल के दूर–दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस माध्यम से कठिन इलाके और सीमित पहुंच की चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन द्वारा खेतों और फसलों पर दबाइयों के स्प्रे में भी इनका विशेष उपयोग होता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना को हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित UAV' दृष्टि 10 स्टार लाइनर' उपलब्ध हुआ। यह भारत की एक प्रमुख निजी कम्पनी अडानी डिफेंस एण्ड ऐरोस्पेस ने बनाया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने इसकी विशेष सराहना करते हुए यह कहा कि संघर्ष के समय समुद्री सुरक्षा के लिए ड्रोन श्आसमान में तीसरी आंख' साबित हो सकता है। दृष्टि 36 घण्टे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है और यह 450 किलोग्राम पेलोड वाली क्षमता का मानवरहित ड्रोन है। इस ड्रोन को STANAG 4671 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, इसके चलते यह नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय सेना को 4 MALE ड्रोन की आपूर्ति के लिए अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस से अनुबन्ध किया था, जिनमें इन्हें दो–दो अगले कुछ महीनों में ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे। सैन्य ड्रोन उद्योग में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत सामयिक है, जो भारतीय रक्षा को सामरिक लाभ और नई ऊंचाई प्रदान करेगा। कई सरकारी और निजी संस्थानों में ड्रोन से जुड़े हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने फरवरी 2021 में भारत की पहली ड्रोन फ्लाइंग साइट पर DGCA प्रमाणित प्रशिक्षण शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरण के लिए 120 करोड़ रूपये के लागत की PLI स्कीम को मंजूरी दी है। 2022–23 के बजट में ड्रोन शक्ति योजना की भी घोषणा की गई थी, इसके तहत

ड्रोन–एस–ए–सर्विस के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ सभी राज्यों में चुनिंदा प्ज्प् में कौशल विकास के लिए ड्रोन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इस समय भारत में ड्रोन के निर्माण के लिए 333 स्टार्ट–अप स्थापित हो चुके हैं, और देश के नौजवानों और उधमियों द्वारा और नी तेजी से विकसित किये जा रहे हैं। पड़ोसी देशों में बढ़ती चुनौतियों और भू–रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत इस क्षेत्र में जल्द से जल्द आत्मनिर्भरता हासिल करे। इसके लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना जरूरी है। जैसे–जैसे दुनियाभर में प्रगति हो रही है भारत पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस दृष्टि से भारत में जहां आत्मनिर्भरता के लिए क्त्क्व् और पब्लिक सेक्टर में ड्रोन निर्माण और टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर द्वारा इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ ही मित्र देशों से भी उच्च तकनीक और संयुक्त निर्माण के लिए करार किये जा रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के साथ रक्षा समझौते में भारत ने प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था। इस वर्ष भारत अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह में देश के सैन्य बल और सुरक्षा उपकरणों का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ।

# सौर क्रांति की शुरुआत, सूर्योदय योजना ने दिया नया जीवन

सुशील

आंकड़े गवाह हैं कि भारत को जितने कच्चे तेल की जरूरत है, उसके 86 फीसदी से ज्यादा का वह आयात करता है। दरअसल, भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का तकरीबन आधा हिस्सा कोयला–आधारित है। ऐसे में, अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन करे, ताकि कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन मिलता रहे। लेकिन इससे होने वाले वायु प्रदूषण का क्या, जो खासकर शहरों के निवासियों के लिए प्राणघातक बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक ऊर्जा की कुल मांग का 25 फीसदी हिस्सा अगले दो दशकों में भारत से होने की उम्मीद है। जाहिर है कि ये आंकड़े सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। भारत के ज्यादातर हिस्सों में साल के तीन सौ दिनों तक धूप रहती है। यही वजह है कि सौर ऊर्जा उत्पादन को 70 गीगावॉट से ज्यादा बढ़ाते हुए भारत सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर है और 2030 तक इसका 280 गीगावॉट बिजली पैदा करने लक्ष्य भी है। इसमें कतई संदेह नहीं कि वर्तमान क्षमता और इस लक्ष्य के बीच अंतराल बड़ा है। लेकिन यह भी गौर करने लायक है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा मूल्यांकित 748 गीगावॉट क्षमता का फकत दसवां हिस्सा ही फिलहाल उपयोग में लाया जा रहा है। बदलाव की क्रांति के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने होते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की कहानी महज मेगावॉट की महत्वाकांक्षाओं में सिमट गई है, जिनमें रूफटॉप सोलर क्रांति खो–सी गई है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद का अनुमान है कि भारत में आवासीय छतों पर सोलर रूफटॉप के जरिये करीब 637 गीगावॉट बिजली पैदा की जा सकती है। जाहिर है कि हम महत्वपूर्ण लक्ष्यों से चूक रहे हैं। 2015 में सरकार ने रूफटॉप सोलर के लिए 2022 तक 40 गीगावॉट का लक्ष्य रखा था। लेकिन 2023 के अंत में कुल ऊर्जा उत्पादन में रूफटॉप सोलर की हिस्सेदारी 11 गीगावॉट से कुछ ही ज्यादा रही और इसका ज्यादातर हिस्सा चार राज्यों तक सीमित रहा। हाल ही में मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना (पीएमएसवाई) की घोषणा की, जिसके तहत एक करोड़ घरों की छत पर सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस घोषणा के बाद उम्मीद है कि इनकी लागत में भी कुछ कमी आएगी। महत्वपूर्ण यह भी है कि इससे एक करोड़ घरों के अनुभव के आधार पर आगे के विस्तार के लिए नीति को संशोधित करने का भी अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत की जनसंख्या करीब 1.4 अरब है। अगर हम हर परिवार में पांच लोगों का औसत लेकर चलें, तो इसका अर्थ होगा कि देश में करीब 28 करोड़ परिवार हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में परिवार सवा तीन लाख गीगावॉट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। यानी प्रति व्यक्ति औसत खपत 1,255 किलोवॉटध् घंटे होगी। स्वाभाविक है कि शहरी परिवारों में बिजली की खपत ज्यादा भी होगी। शहरीकरण की गति, कंप्यूटरध् मोबाइल इत्यादि उपकरणों का बढ़ता उपयोग, डिजिटलीकरण इत्यादि को देखते हुए इसमें संदेह नहीं कि बिजली की खपत और मांग, दोनों बढ़ेंगी। भारत की एक–तिहाई आबादी शहरों में रहती है और इनमें 53 शहर ऐसे हैं, जहां दस लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। कस्बों की संख्या चार हजार है। ऊर्जा सुरक्षा की कोई भी पहल मौजूदा और नई इमारतों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मांग करती है। गौरतलब है कि यूरोप के देशों ने 2028 तक नई और मौजूदा इमारतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के घटक को अनिवार्य कर दिया है। रियल एस्टेट (विनिमयन और विकास) अधिनियम और नगरपालिका के नियमों के तहत सरकार सभी नए आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना को अनिवार्य कर सकती है। हालांकि रूफटॉप सोलर का विस्तार इस संबंध में बनने वाली नई नीति के स्वरूप पर भी निर्भर करता है। यह न मानने का कोई आधार नहीं है कि लागत व व्यवधान कम करने और प्रदूषण फैलाने वाले जेनरेटर से छुटकारा पाने के लिए लोग प्रभावी व स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प चुनना पसंद करेंगे। रूफटॉप सोलर पर दिए जा रहे जोर के पीछे के अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत है। निजी स्तर पर देखें तो घरों में, छोटे व्यवसायों को इससे सस्ती बिजली मिलेगी और ब्लैक आउट से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी और अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि तीन किलोवॉट के रूफटॉप संयंत्र का इंस्टालेशन सहित कुल खर्चा करीब तीन लाख रुपये है, जिसमें 40 फीसदी सब्सिडी का भी प्रावधान है। हालांकि ज्यादा क्षमता का संयंत्र चाहने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के लिए यह खर्च जरूर बढ़ जाएगा और उन्हें सब्सिडी भी कम मिलती है। नेट मीटरिंग फॉर्मूले को लेकर, जिसके तहत सौर ऊर्जा से प्राप्त अधिशेष बिजली को ग्रिड को लौटा कर, उससे क्रेडिट पाया जा सकता है, विद्युत वितरण कंपनियां पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। शायद इसीलिए, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक सुनवाई में राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने तर्क दिया कि छत पर सोलर संयंत्र उपभोक्ताओं द्वारा खुद के उपयोग के लिए लगाया जाता है, इसलिए अधिशेष बिजली के निर्यात को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी बुरी बात यह है कि रूफटॉप सोलर के लिए कर्ज पर ब्याज दर दस फीसदी से ज्यादा है।

# मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में वापसी के भरोसे की झलक

आसिफ

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अपने छठे बजट और पहले अंतरिम बजट को पेश करते हुए साफ संदेश दिया कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर पूरी तरह न सिर्फ आश्वस्त है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था जो रोड मैप उसने अब तक तैयार किया है, उसी पर आगे बढ़ने के लिए भी दृढ़ संकल्प है। इस अंतरिम बजट में यह संदेश भी निहित है कि पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दमदारी से आगे बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। चूंकि यह अंतरिम बजट था, इसलिए इसमें किसी तरह की लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाओं की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। खुद वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखते हुए अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि, बजट में थोड़ी बहुत राहते तो हैं। पूरा बजट मोदी सरकार दो माह बाद लोकसभा चुनाव में नया जनादेश लेकर प्रस्तुत करेगी। लेकिन वह भी अंतरिम बजट का विस्तार होगा, जिसमें देश में 'विकसित भारत' की अवधारणा के साथ देश के आर्थिक विकास का रोड मैप होगा। छोटा होने के बाद भी इस अंतरिम बजट में पूर्ण भावी बजट के संकेत छुपे है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह देश के निर्माण का बजट है। हालांकि, इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इस बजट के माध्यम से देश की प्रमुख समस्याओं जैसे कि बढ़ता कर्ज, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आदि का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के संकट के संदर्भ में देखें तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने देश की गुलाबी तस्वीर पेश करने का भरपूर प्रयास किया है। यह भी सच है कि देश की विभिन्न आंतरिक और बाहरी समस्याओं के बाद भी भारत की आर्थिकी अपनी चाल से आगे बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोगों के हाथ पैसा आए। लेकिन पूर्ण बजट में हमे ऐसे प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। यूं यह बजट अपने साथ कुछ रिकॉर्ड भी बना गया है। पहला तो देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री होते हुए लगातार छठी बार बजट पेश करने का और अपने ही पूर्ववर्ती भाषणों की तुलना में सबसे छोटा यानी 58 मिनट का भाषण देने का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद जब निर्मला सीतारमन को अपना वित्त मंत्री बनाया था, तब उनकी क्षमताओं को लेकर कई सवाल भी तैर रहे थे, क्योंकि इस देश में कुछ समय के लिए वित्त मंत्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल छोड़ दें तो वित्त विभाग पुरूषों का अधिकार क्षेत्र रहा है। एक त्रासदी यह भी रही कि निर्मला सीतारमन के वित्त मंत्री बनने के एक साल बाद ही देश को कोविड से जूझना पड़ा, जिससे देश की आर्थिकी काफी गड़बड़ाई। लेकिन अब यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कोविड के बाद वे फिर देश की आर्थिकी को काफी हद तक पटरी पर ले आई हैं और यह अंतरिम बजट भी आत्मविश्वास से भरा है। यह अंतरिम बजट मुख्यतः आर्थिक विकास की गति को कायम रखने और गरीब कल्याण के भाव से प्रेरित है, जो मुख्य रूप से 4 सेक्टरों पर फोकस है। ये हैं– गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। सरकार को मालूम है कि चुनाव में मतदान की दृष्टि से इन्हीं वर्गों का महत्व सर्वाधिक है और इनके वोटों से ही सरकार के सत्ता में लौटने की आश्वस्ति भी बनती है। लिहाजा यह राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय वित्तमंत्री ने दावे के साथ कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी घट रही है। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण योजना में रू 34 लाख करोड़ खातों में भेजे। इसी तरह वित्तमंत्री ने दावा किया आज देश में करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं हैं, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। युवाओं में कौशल विकास का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि देश में तीन हजार नए आईआईटी खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान और रोजगार की दृष्टि से लागू पीएम किसान योजना का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कराधान प्रणाली, रक्षा बजट में वृद्धि तथा अन्य योजनाओं के संदर्भ में कहा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जबकि रक्षा खर्च में 11.1: की बढ़ोतरी की गई है। देश का रक्षा खर्च अब जीडीपी का 3.4: होगा। इसी तरह आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने, तिलहन अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया। जहां तक मध्य वर्ग को कर राहत की बात है तो वित्त ने आयकर के वर्तमान स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और न ही कोई नए टैक्स लगाए। अलबत्ता देश में कर संग्रहण की गुलाबी तस्वीर उन्होंने जरूर पेश की। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। बजट में बढ़ता राजकोषीय घाटा चिंता का विषय है। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि वर्तमान राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आगे हम इसे और कम करेंगे। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। प्रस्तुत अंतरिम बजट में 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। विदेशी निवेश का जिक्र करते हुए सीतारमन ने कहा कि बीते 10 साल में देश में दोगुना एफडीआई आया। कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से बजट में कारपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है। बजट में रेलों की गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से वित्तमंत्री ने घोषणा की कि 40 हजार सामान्य रेल कोचेज वंदे भारत जैसे होंगे, ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी, सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देगी। पिछले दिनो पड़ोसी देश मालदीव के सात रिश्ते तनावपूर्ण होने के बाद मोदी सरकार ने भारतीय समुद्री सीमा में स्थित लक्षद्वीप में अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1: ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है। साथ ही उन्होंने 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देने की बात भी कही। बजट में महिलाओं–बच्चों, मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया है।

# वाराणसी समेत पूर्वांचल में चुराते हैं मोबाइल, गिरोह का एक आरोपी अरेस्ट

वाराणसी, संवाददाता। वाराणसी शहर और पूर्वांचल में चोरी हुए मोबाइल सेट को झारखंड के तालझाड़ी, राजमहल आदि इलाकों में बेचा जाता है। मोबाइल चोरी के लिए झारखंड में किशोरों और युवाओं को तीन माह की ट्रेनिंग देकर यहां भेजा जाता है। तालझाड़ी में दबिश देना पुलिस के लिए आसान नहीं है। यहां जाने के लिए तीन किमी के ताल को नाव से पार करना पड़ता है। मोबाइल चोरी के अंतरराज्यीय गिरोह के एक बदमाश को कैंट जीआरपी ने पकड़ा है। आरोपी ने बताया कि उसके गिरोह के 12 किशोर मोबाइल चोरी करते हैं। जीआरपी कैंट के अनुसार गिरोह के बदमाश शहर के भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों, सरकारी अस्पतालों, मंदिरों और रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल चोरी करते हैं। मोबाइल चोरी करने के बाद तय स्थान पर इकट्ठा होते हैं और मोबाइल झारखंड पहुंचाते हैं। सभी सुंदरपुर, खोजवां, कैंट समेत अन्य क्षेत्रों में किराये के कमरे और सस्ते लॉज में अपना ठिकाना बनाए हैं। कैंट जीआरपी के एक इंस्पेक्टर ने बताया कि झारखंड के तालझाड़ी, राजमहल थाना क्षेत्र में तीन हजार रुपये में मोबाइल बेची जाती है। चोरी का मोबाइल झारखंड में एक मोबाइल डीलर दो हजार रुपये में खरीदता है। तालझाड़ी में जल्दी कोई पहुंच नहीं सकता है। गांव में पहुंचने के लिए तीन किमी नाव से सफर करना पड़ता है। चोरी करने की गांव में ट्रेनिंग दी जाती है। जीआरपी के अनुसार मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि पुलिस और जीआरपी की लोकेशन उनके पास होती है। यदि गिरोह का कोई सदस्य पकड़ा जाता हैं तो उसे छुड़ाने के लिए अधिवक्ता पहुंच जाते हैं। नाबालिग होने के कारण तुरंत जमानत मिल जाती है।

आईफोन के पार्ट्स अलग–अलग करके बेचे जाते

चोरी के आईफोन के पार्ट्स अलग–अलग करके बेच दिए जाते हैं। 60 से 80 हजार का मोबाइल के पार्ट्स अलग–अलग करके बेचने पर 40 से 50 हजार रुपये मिलते हैं। जबकि आईफोन चोरी करने वाले को डीलर महज दो हजार रुपये देता है।

क्या कहते हैं अधिकारी

मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का कनेक्शन झारखंड के तालझाड़ी समेत अन्य क्षेत्रों से है। गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा गया है। आरोपी के पास से मोबाइल बरामद हुआ है।

# नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया अल्टीमेटम

गोरखपुर, संवाददाता। शहीद बंधु सिंह पार्क में बनने वाली मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण काम 6 फरवरी से शुरू होगा। नगर निगम से आवंटित दुकानदारों को पांच फरवरी तक दुकान खाली करने का समय दिया गया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को बाजार की दुकानों के बाहर नोटिस चस्पा कर दुकानदारों को भी जानकारी दे दी गई है। तय समय अवधि के बीतने और दुकानें खाली नहीं होने नगर निगम इन दुकानों को खाली करवाएगा। जल निगम की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि बंधू सिंह पार्क में मौजूद सभी दुकानों को खाली करने के संबंध में सराफा मंडल, मंदिर समिति एवं बंधू सिंह पार्क के व्यापारियों से बैठक में आम सहमति से बंधू सिंह पार्क में स्थित सभी दुकानों को खाली करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी। यह समय सीमा पांच फरवरी को खत्म हो रही है। सभी दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी–अपनी दुकानों को 5 फरवरी तक निश्चित रूप से खाली कर दें। ताकि 6 फरवरी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। 5 फरवरी तक दुकान न खाली करने करने वाले दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप है। वहीं, व्यापारियों में नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर निराशा है। 19 जनवरी को सराफा मंडल अध्यक्ष गणेश वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों की बैठक में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने विश्वास दिलाया था कि मल्टीलेवल पार्किंग में बनने वाली दुकानों के आवंटन में प्रभावित कारोबारियों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन, व्यापारियों को अभी तक लिखा पढ़ी में कोई सहमति नहीं दी गई है। वहीं, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि दुकानदारों को दुकान खाली करने के बारे में कहा जा चुका है। बैठकर उनके साथ लगभग सभी मुद्दों पर बातचीत हो चूकी है। 15 दिनों का समय मांगा गया था तो निगम ने व्यापारियों की सहूलियत के लिए सम भी दे दिया है।

# गोरखपुर विश्वविद्यालय की पोर्टल पर बढ़ा फीस देख छात्र परेशान

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछले सत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में फीस की बढ़ोत्तरी की गई थी। विश्वविद्यालय की कुलपति ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुराने छात्रों को बढ़ी फीस से मुक्त करने का निर्देश दिया। सेमेस्टर परीक्षा के बाद जब इस सत्र में छात्र फीस जमा करने के लिए पोर्टल खोले तो बढ़ी फीस दिखने पर वे अवाक रह गए। बुधवार को उन्होंने कुलपति से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। कुलपति कार्यालय पर बुधवार की दोपहर पहुंचे बीए–एलएलबी द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) के छात्रों ने कुलपति से मुलाकात की। कुलपति को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनका निर्धारित फीस 34500 रुपये है, जिसमें से 20 हजार रुपये वे तृतीय सेमेस्टर में जमा कर चुके हैं। शेष धनराशि 14500 रुपया उनको जमा करना है। उन्होंने विश्वविद्यालय की पोर्टल चेक की तो अभी भी बढ़ी फीस 18000 रुपये दिख रही है। कुलपति ने जल्द फीस में संशोधन कराने व अंतिम तिथि बढ़ाने का आश्वासन दिया।

तिथि आठ फरवरी तक बढ़ी

शैक्षिक सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित, परास्नातक एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में संचालित नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा परास्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के प्रवेश व पंजीकरण फार्म पूरित कर जमा करने की तिथि एक बार फिर बढ़ गई है। कुलपति के निर्देश के क्रम में अब आठ फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह जानकारी कुलसचिव प्रो.शांतनु रस्तोगी ने दी। बताया कि इसके बाद कोई तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। जिन विद्यार्थियों द्वारा इस अवधि में आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे, वे किसी भी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे।

# धर्म परिवर्तन के मामले में भी शुआट्स कुलपति आरबी लाल की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, संवाददाता। धर्म परिवर्तन और रंगदारी के आरोप में जेल में बंद शुआट्स विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आरबी लाल की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय से खारिज हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य आरोपी प्रो. आरबी लाल और सह आरोपी राम सेवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। नैनी स्थित सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस (शुआट्स) के कुलपति प्रो. आरबी लाल के खिलाफ धर्म परिवर्तन, रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। नवाबगंज में दर्ज मुकदमे में विवेचना के दौरान उनका नाम प्रकाश में आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। 11 दिसंबर 2023 को नवाबगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें रामसेवक सरोज को नामजद किया गया था, जबकि, उसके अज्ञात साथी भी आरोपी बनाए गए थे। इसमें प्रार्थना के नाम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने, हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने व गालीगलौज के आरोप लगाए थे। पुलिस ने रामसेवक को एफआईआर दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि रामसेवक कुलपति आरबी लाल का सहयोगी था और उसके ही इशारे पर काम करता था। आरोपी के बयान से भी पुलिस के हाथ कई अहम तथ्य सामने आए। विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर संलिप्तता पाते हुए आरबी लाल का नाम भी प्रकाश में लाया गया और उसे भी मुकदमे में आरोपी बनाया। पहले से जेल में बंद आरबी लाल के मुकदमे में इसका तामीला कराया गया।

यह था पूरा मामला

जिस मुकदमे में यह कार्रवाई हुई, वह युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार निवासी नौगवां का पूरा, अटरामपुर नवाबगंज ने लिखाया था। उसने आरोप लगाया था कि 10 दिसंबर को वह अपने साथी विनोद गौड़ निवासी बुदौना कौड़िहार के साथ पार्टी के काम से ग्राम पचदेवरा गया था। शाम सात बजे के करीब यीशू दरबार का संचालक रामसेवक अपने साथियों के साथ उसे मिला और कहने लगा कि बड़े नेता बनते हो और मेरा विरोध करते हो। विरोध करने पर गालियां देने लगा और बोला कि मैं दरबार संचालित कर रहा हूं, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो तुम भी साथ में आ जाओ। विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से फायर किया जिसमें वह बाल–बाल बच गया। इसके बाद आरोपी ने भागते हुए कहा कि जान बचाना चाहते हो तो एक लाख रुपये पहुंचा दो। वादी का यह भी आरोप है कि रामसेवक हिंदुओं का प्रार्थना के नाम पर अवैध रूप से धर्मांतरण कराता है। अंधविश्वास फैलाकर लोगों को कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक करने की गारंटी लेता है जिससे कई लोग असमय जान भी गंवा रहे हैं।

30वें मुकदमे में बनाए गए आरोपी

यह 30वां मुकदमा है जिसमें शुआट्स वीसी आरोपी बनाए गए हैं। उन पर पहला मुकदमा 1998 में दर्ज हुआ। चार साल पहले भी 22 करोड़ के गबन के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 1998 में पहला मुकदमा नैनी थाने में गालीगलौज व धमकी देने के आरोप में दर्ज हुआ। 2011 में हत्या के प्रयास, साक्ष्य छिपाने व आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने के मुकदमे में उन्हें आरोपी बनाया गया।

# पिकअप से जोरदार टक्कर के बाद बोलेरो के उड़े परखच्चे

बलिया, संवाददाता। बलिया जिले के नगरा मार्ग पर गुरुवार की सुबह बिड़हरा ग्राम के समीप बोलेरो और पिकअप की आमने–सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, बोलेरो सवार चार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान मार्ग से गुजर रहा बालक दुर्घटना की चपेट में आने से जीवन–मौत के बीच जूझ रहा है। सीएचसी से सभी घायलों को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

मऊ जिले के मर्यादपुर (डुमरी) से बोलेरो पर सवार चालक समेत आधा दर्जन लोग बक्सर में किसी रिश्तेदार की हुई मौत में पुछार करने के लिए नगरा मार्ग होकर जा रहे थे। इस दौरान नगरा की ओर से तेज गति से मुर्गी लदी पिकअप कोहरे के चलते विपरीत दिशा से जा रहे बोलेरो से टकरा गई। पिकअप और बोलेरो की टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। चालक सूर्यकेश राजभर (55) पुत्र रामरूप निवासी महुई थाना मधुबन (मऊ) की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। बोलेरो पर सवार बिंदा देवी (40) पत्नी महातम, अनिल कुमार (50), गीता देवी (48) पत्नी अनिल, रामबाबू (50) और महातम (45) घायल हो गए। साइकिल सवार उभाव थाना क्षेत्र के निवासी सूरज (12) पुत्र वीरेंद्र घायल हो गए। हादसे के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाया गया, जहां बिंदा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरज व गीता देवी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मुर्गी लदी पिकअप लेकर चालक भाग निकला। हालत की चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया।

# बहुमुखी प्रतिभा के धनी 34 वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी सेनानायक डा मिश्र को जवानों ने नम आंखों से दी भव्य बिदाई

## –बताते चलें डा मिश्र बने डीआईजी पीएसी सेक्टर कानपुर।

(राजेश श्रीवास्तव
ब्यूरो चीफ अयोध्या)

अयोध्या। मीडिया सेल 34 वी वाहिनी पीएसी वाराणसी के मुताबिक करीब साढ़े तीन वर्ष से अधिक अवधि तक सेनानायक 34 वीं वाहिनी पीएसी के रुप में दायित्व संभालने के बाद अब डाक्टर राजीव नारायण मिश्र का डीआईजी पीएसी कानपुर सेक्टर के लिए स्थानांतरण हो गया।जिसके चलते 34 वी वाहिनी पीएसी वाराणसी के अधिकारियों व जवानों ने सेनानायक डॉ मिश्र की विदाई समारोह को यादगार बना दिया।34वी वाहिनी के अधिकारियों व कर्मियों ने कहा कि कुछ अधिकारी अपने काम और व्यवहार से अपनी अलग पहचान बना लेते हैं,उनका ऐसा प्रभाव होता है कि उनके ट्रांसफर पर अक्सर कर्मचारी उदास हो जाते हैं। अपने व्यवहार और कुशल कार्यशैली के चलते आमजन से सीधा जुड़ाव रखने वाले डॉ राजीव नारायण मिश्र के विदाई समारोह में पुलिस कर्मचारियों के साथ–साथ खुद डॉ मिश्र भावुक हो गए। बुधवार को विदाई समारोह में पुलिस अधिकारियों ने उनका अभिनंदन कर उन्हें विदाई दी।वाहिनी में डॉ मिश्र द्वारा कराए गए कार्यों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बताते चलें कि वर्तमान में डीआईजी डॉ मिश्र,प्रयागराज में माघ मेले का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हैं।इस विदाई के मौके पर 34 वी वाहिनी मुख्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

# संगमनगरी से रामनगरी का सफर होगा छोटा, प्रयागराज-अयोध्या धाम रेलखंड का होगा दोहरीकरण

प्रयागराज, संवाददाता। संगमनगरी से रामनगरी का सफर अब और छोटा हो जाएगा। इन दोनों ही शहरों को जोड़ने वाली रेललाइन के दोहरीकरण का निर्णय रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया है। प्रयागराज से अयोध्या धाम के बीच रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य इसी वर्ष शुरू भी हो जाएगा। दोहरीकरण का कार्य होने के बाद ट्रेन द्वारा तकरीबन तीन से साढ़े तीन घंटे में ही अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम की कुल दूरी 160 किलोमीटर है। इस रूट पर अभी प्रयागराज जंक्शन से फाफामऊ जंक्शन तक ही रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है। फाफामऊ से अयोध्या धाम के बीच कुल 151 किमी रेलमार्ग का दोहरीकरण किया जाना है। वर्ष 2022 में ही प्रयागराज से अयोध्या के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज द्वारा किया गया था। वर्तमान समय प्रयागराज से अयोध्या के बीच कुल पांच ट्रेनें संचालित हैं। यह सभी ट्रेनें साढ़े चार से साढ़े पांच घंटे का वक्त अयोध्या पहुंचने में लेती है, लेकिन दोहरीकरण के बाद यह सफर तीन से साढ़े तीन घंटे में पूरा हो सकेगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इसी वजह से रेल मंत्रालय ने तय किया है प्रयागराज– प्रतापगढ़– सुल्तानपुर– अयोध्या रेलमार्ग का दोहरीकरण हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम रेल बजट पेश करने के बाद वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मीडिया से रूबरू हुए रेलमंत्री ने बताया कि अयोध्या से प्रयागराज तक के रेलमार्ग का दोहरीकरण किया जाएगा। यह कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा।

दस वर्ष में तैयार किए 1377 रेल ओवर ब्रिज एवं अंडर पास

यूपी में चल रहे रेलवे के कार्यों के लिए इस बार पीएम मोदी ने अपना खजाना खोल दिया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए रेलवे द्वारा किए जाने वाले तमाम कार्यों के लिए पीएम ने प्रदेश 19575 करोड़ रुपये का बजट दिया है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में जीएम एनसीआर रविंद्र गोयल, डीआरएम हिमांशु बडोनी आदि अफसरों एवं मीडिया कर्मियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेसिंग में रेलमंत्री ने बताया कि यूपीए शासनकाल में वर्ष 2009–14 के दौरान यूपी को हर वर्ष रेलवे के लिए 1109 करोड़ रुपये ही मिलते थी। उसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मोदी सरकार ने यूपी में चल रहे विभिन्न कार्य के लिए 19525 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यहां बीते दस वर्ष में 1377 रेल ओवर ब्रिज, अंडर पास का निर्माण हुआ है। प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ समेत प्रदेश के 157 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा 142 स्टेशन पर वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट के तहत स्थानीय उत्पादों को बेचा जा रहा है। इसके पूर्व जीएम एनसीआर रविंद्र गोयल ने कवच को लेकर किए जा रहे कार्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 तक एनसीआर के चुने गए 54 में से आठ स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित कर लिए जाएंगे। शेष अन्य स्टेशन दिसंबर 24 तक कंपलीट हो जाएंगे। इस अवसर पर सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला, सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय, सचिव जीएम अजय सिंह, डा. अमित मालवीय, अमित कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। प्रयागराज के सूबेदारगंज से सिकंदराबाद के लिए चल रही वीकली स्पेशल के रेलवे ने फेरे बढ़ा दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन 28 मार्च तक होगा।

# सिद्धार्थनगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटा एक की मौत

सिद्धार्थनगर, संवाददाता। सिद्धार्थनगर जिले में उसका थाना क्षेत्र के गोरखपुर–नौगढ़ एनएच पर स्थित पकड़ी चौराहे पर बृहस्पतिवार दोपहर प्लाई लदा ट्रक टेंपो पर पलट गया। इस हादसे में टेंपो चालक की मौत हो गई। जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में तीन एक ही परिवार के हैं और एक ट्रक चालक बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। महराजगंज जनपद के सहजनवा बाबू गांव निवासी सुधीर सिंह (50) पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पालिका सिद्धार्थनगर में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। रात में पंप चलाते थे और दिन में टेंपो चलाते थे। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को नौगढ़ से उसका के लिए निकले थे और पकड़ी चौराहे पर सवारी बैठाने के लिए खड़े थे। नौगढ़ से ही पांच सवारी टेंपो में सवार थे। चलने वाले थे कि तभी एक प्लाई लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और टेंपो उसी के नीचे दब गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से प्लाई हटाकर टेंपो में सवार लोगों को बाहर निकाल कर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चालक सुधीर सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जोखन निवासी रामगढ़वा थाना बृजमनगंज जो टेंपो में बैठा था।

# सपा विधायक ने दरोगा पर लगाया गंभीर आरोप

प्रयागराज, संवाददाता। हंडिया के सपा विधायक हाकिम लाल बिंद ने हंडिया कोतवाली अंतर्गत आने वाले बरौत पुलिस चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाया है। सपा विधायक की शिकायत का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ने आरोप लगाया कि शांति भंग जैसी धाराओं में भी बरौत चौकी इंचार्ज के द्वारा दस–दस और बीस–बीस हजार रुपये की वसूली एक दलाल के माध्यम से कराई जा रही है। वह आगे कहते हैं कि लिखित और मौखिक शिकायत के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विधायक ने भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि भाजपा सरकार में जब लोकतंत्र पर ही आघात किया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति कहां कार्य करेगी।

कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

सपा विधायक ने कहा कि गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी से चौकी इंचार्ज की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है। आरोप लगाया कि दरोगा लोगों से घूम–घूम कर कह रहा है कि हाकिमलाल सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं, वह विपक्ष के विधायक हैं। मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। विधायक बोले कि आए दिन बरौत क्षेत्र की जनता धन उगाही की शिकायत लेकर आ रही है। 151 जैसे मामले में भी दरोगा मोटी वसूली से नहीं बाज आ रहे हैं। कहा कि अगर दलाल के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

# सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन चार को

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच की ओर से रविवार 4 फरवरी को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार पटेल और सामाजिक समरसता से जुड़े विभिन्न पक्षों पर राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस होगे। बौद्धिक विचार मंच के महामंत्री जगदीश शरण गंगवार ने बताया कि पटेल समाज की आबादी 12 प्रतिशत से अधिक है। ये ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि, मुख्य रूप से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान कुलपति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, सांसद, विधान सभा व विधान परिषद सदस्य, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सहकारी बैंको के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, उद्ध्योगपति, अधिवक्ता, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, समाज सेवी, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रोग्रेसिव किसानों सहित लगभग 2,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोजित पत्रकार वार्ता में अरुण कुमार सिन्हा आईएएस सेवानिवृत्त संस्थापक संरक्षक डॉक्टर क्षेत्रपाल गंगवार अध्यक्ष, वी आर वर्मा एवं रविन्द्र कुमार गंगवार उपाध्यक्ष, उमेश कुमार सिंह महामंत्री एवम आर एल निरंजन कोषाध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बताया कि उक्त सम्मेलन में मुख्य रूप से सरदार पटेल और आधुनिक समाज, सामाजिक समरसता, पिछड़ा वर्ग, कृषकों एवं सर्वहारा समाज, रोजगार उन्मुखी जागरुकता, शिक्षा और प्रचलित अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों की प्रासंगिकता जैसे विषयों के अलावा समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार होगा। सम्मेलन में किसी राष्ट्रीय मार्ग का नाम सरदार पटेल के नाम पर किये जाने का प्रस्ताव पारित होगा। साथ ही लखनऊ और दिल्ली में पटेल स्मारक बनवाने, हर जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने समाज में अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कार, बुद्धिजीवी एप और पटेल चेतना रैली आदि पर विचार विमर्श करते हुए आगामी रणनीति तय की जायेगी। बताते चलें कि सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का गठन जुलाई 2018 में किया गया था। मंच के मुख्य उद्देश्य समाज को अपने हितों के प्रति जागरुक करना, समाज की विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों को एक मंच पर इकठ्ठा करना, संख्या के आधार पर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भागीदारी हेतु प्रयास करना, समाज में अधिकाधिक उद्यमी बनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण अंचलों में पुस्तकालय, वाचनालय एवं इनसे जुड़ी गतिविधियों का संचालन कराना हैं। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंच द्वारा विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जा चुके हैं। जैसे प्रदेश के 15 मंडलों और दिल्ली में प्रेस वार्ताएं आयोजित की गयीं। विचार मंच द्वारा बुद्धिजीवी चिंतन शिविर, सरदार पटेल एवं ग्राम्य विकास कार्यक्रम, पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह, सामाजिक चिंतन शिविर, अपनों से मिलिए, सरदार सम्मान समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किये जा चके हैं। उक्त कार्यक्रमों की कड़ी में ही 4 फरवरी का कार्यक्रम आयोजित हैं।

# छात्र की पिटाई की घटना का आडियो वायरल

प्रयागराज, संवाददाता। तीन दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रॉक्टोरियल बोर्ड पर पिटाई, गालीगलौज करने वाले छात्र अभिषेक गुप्ता ने बुधवार को एक ऑडियो वायरल किया। आरोप है कि यह ऑडियो उसी घटना का है जिसमें प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्य उससे मारपीट व गालीगलौज करते सुने जा सकते हैं। उधर चीफ प्रॉक्टर का कहना है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं और अगर कोई ऑडियो है तो उसमें उनकी आवाज नहीं। 19 मिनट के इस ऑडियो में एक व्यक्ति रो–रोकर खुद को माफ किए जाने की बात कहता सुनाई पड़ता है। जबकि कुछ लोग उसे पीटते–गालीगलौज करते व धमकाते सुनाई पड़ते हैं। एसएसएल हॉस्टल के अंतरूवासी अभिषेक गुप्ता का आरोप है कि इसमें रो–रोकर माफी मांगने वाला वह खुद है और दूसरी ओर से गालीगलौज, पिटाई करने व धमकी देने वाले प्रॉक्टोरियल बोर्ड के चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह, अतुल नारायण सिंह, विवेक द्विवेदी व मृत्युंजय राव परमार हैं।

# वूल्वरिन फूड्स ने टेस्ट्री मसाला किया लान्च, खाने के शौकीनों को मिलेगा स्वाद का असली आनंद

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। गुरुवार को राजधानी के गोमतीनगर इलाके में आयोजित के भव्य कार्यक्रम में, वूल्वरिन फूड्स ने अपने नए प्रोडक्ट टेस्ट्री मसाला के लॉन्च की घोषणा की। यह कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में नवीनतम जुड़ाव है। वूल्वरिन फूड्स फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। कंपनी अब टेस्ट्री ब्रांड के तहत मसालों, अचार, सॉसेज और रेडी–टू–मेक डेसर्ट की एक श्रृंखला पेश करके उपभोक्ता बाजार में उतर रही है। लॉन्च के अवसर पर टेस्ट्री के ब्रांड एंबेसडर, सेलिब्रिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने एक इंटरैक्टिव लाइव कुकिंग सेशन के दौरान अपने असाधारण पाक कला कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा ष्टेस्ट्री मसाला सिर्फ एक मसाला नहीं हैय यह एक विशुद्ध भारतीय स्वाद की यात्रा है जिसका आनंद खाने के शौकीनों को भरपूर मिलेगा। वूल्वरिन फूड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमर कपूर ने इस लॉन्च के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा ष्हमारा लक्ष्य खाने के शौकीनों को मसालों की प्रामाणिक सुगंध और स्वाद प्रदान करना है, जिससे हर रेसिपी में स्वाद का सही मिश्रण मिलता है। वूल्वरिन फूड्स के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रशांत बाजपेयी ने कहा, बाजार में 20 से अधिक वर्षों की उपस्थिति के साथ, हम बाजार में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेस्ट्री के अग्रणी प्रोडक्ट के रूप में स्थापित होने के लिए आश्वस्त हैं। इस लॉन्च प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों को विस्तृत प्रेजेंटेशन के अलावा टेस्ट्री मसालों से तैयार व्यंजनों का स्वाद चखने और शेफ के बातचीत कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने कुकिंग टिप्स सीखने का भी अवसर भी मिला।

# पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा मासिक स्मृति–पत्र धृति का किया गया विमोचन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा जारी की जाने वाली मासिक स्मृति–पत्र धृति का विमोचन किया गया तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा प्रदेश सरकार की महिलाओं की सुरक्षा एवं विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्धता दर्शाते हुये अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एन. पद्मजा एवं उनकी टीम के अथक प्रयासों से प्रकाशित की जा रही धृति मासिक स्मृति–पत्र के प्रथम प्रकाशन हेतु शुभकामनायें दी गयीं।

उक्त मासिक स्मृति–पत्र में माह में महिला व बाल सुरक्षा के विषय में की जाने वाली समस्त गतिविधियों जैसे –

– अन्य संगठनों, संस्थानों व इकाईयों के समन्वय से लागू की जाने वाली कार्ययोजनाओ व विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं ।

– महिला व बाल अपराधों पर नियंत्रण हेतु किये जाने वाले संस्थागत प्रयास ।

– लैंगिक हिंसा की घटनाओं के नियंत्रण हेतु अभिनव तकनीकी प्रयोग।

– महिला व बाल अपराधों से जुड़े विशेष अभियान।

– लैंगिक हिंसा के मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान, आदि विषयों पर संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जायेगा।

माह के प्रथम सप्ताह में गत माह की गतिविधियों का स्मृति–पत्र प्रकाशित किया जायेगा जिसे महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की आधिकारिक वेब साईट पर प्रकाशित करते हुए समस्त पुलिस ईकाइयों को ई–मेल पर उपलब्ध कराया जायेगा।इस अवसर पर एन. पद्मजा अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र० विजय त्रिपाठी अपर पुलिस अधीक्षक एवं विनोद यादव पुलिस उपाधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उपस्थित रहे।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों की संख्या में राम नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को होम्यो हाल देवकाली चौराहा की ओर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन

प्रोपराइटर
डा0 पवन श्रीवास्तव
होम्यो हाल देवकाली चौराहा
मो0– 9889560150

प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश-विदेश के कोने कोने से रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को श्री नव दुर्गा प्लाईवुड हार्ड वेयर सेंटर रीडगंज अयोध्या की ओर स्वागत व अभिनंदन

प्रोपराइटर
हिमांशु श्रीवास्तव
मो0– 9721429775

डी पी श्रीवास्तव
मो0– 9415076595

# प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की राम नगरी में हो रही लगातार बढ़ोतरी

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामनगरी में गूंज रही रामधुन के बीच आराध्य के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का आना अनवरत जारी है। देश विदेश से भारी संख्या में यहां पहुंच रहे श्रद्धालु सुव्यवस्थित ढंग से रामलला का दर्शन पाकर निहाल हो रहे हैं। विभिन्न प्रांतों से यहां पहुंच रहे श्रद्धालु दिव्य अयोध्या को निहार कर आह्लादित हैं। बताते चलें गुरुवार को भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विभिन्न प्रदेशों से हजारों की संख्या में रामभक्तों ने रामलला के दर्शन किए।रामनगरी के कोने कोने में रामधुन और जय श्री राम के उद्घघोष के बीच हर रोज विभिन्न प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे है और रामनगरी की वर्तमान चकाचौंध देख आह्लादित हो रहे हैं।गुरुवार को भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हुए दिखे।लोग अपने परिवार के साथ सामान्य तरह से दर्शन को जाते हुए जिला प्रशासन की व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के आए परिवार ने बताया कि बच्चों के साथ आएं हैं। यहां आकर और व्यवस्था देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है।

## उड़नदस्ता ने पकडा वन माफिया, माफीनामा के साथ अठ्ठाइस हजार का वसूला जुर्माना''लंभुआ रेंज के चांदा क्षेत्र बलभद्रपुर का मामला

सुल्तानपुर। जिले में लगातार हरियाली पर वन माफिया प्रहार कर रहे है,सरकार की हराभरा प्रदेश बनाने के स्वप्न को आग लगाई जा रही है,आखिर ऐसा कैसे हो रहा है,इसका उत्तर कौन देगा,वन विभाग या पुलिस विभाग,अफसोस की दोनों मौन है,और इनकी खुली आंखों के सामने सरकार की योजना वनमाफिया तबाह कर रहे है,ऐसा एक दिन भी नही गुजरता जिसदिन जनपद में वृक्ष अवैध रूप से काटे ना जाते हो।ताजा मामला लंभुआ रेंज के चांदा क्षेत्र बलभद्रपुर का है जहा चार फलदार वृक्ष धाराशाही किये गए थे,सूचना पर प्रवर्तन दल पहुंचकर वनमाफियाओं को दबोचते हुए 28 हजार का जुर्माना लगाते हुए भविष्य दोबारा ऐसी गल्ती ना हो मांफीनामा लिखाकर आगे की विभागीय कार्यवाही में जुट गई,बताते चले की वन विभाग द्वारा जनपद में अवैध रूप से चलने वाली आरामशीनों पर प्रभावी कार्यवाई ना करने के कारण वनमाफियाओं के हौसले आसमान पर,है, सदर, कादीपुर, लंभुआ और जयसिंहपुर सभी रेंज में अवैध ढ़ग से आरामशीनें दहाड़ रही है,गनीमत है की इधर पिछले कुछ महीनें से उड़नदस्ताध्प्रवर्तन दल के सक्रीयता के चलते वनमाफियाओं पर काफी कार्यवाहिया हुई और हो रही है,परंतु अभी भी विभाग को बहुत कुछ करना बाकी है।सूत्र बताते है की सदर रेंज में अवैध आरामशीनों की फेहरिस्त लंबी है,इसपर भी कार्यवाही की आवश्यकता है।

# पूर्व सांसद जय भद्र सिंह नही रहे, दिल्ली में ली आखिरी सांस

## –शनिवार को पैतृक गांव मायंग में होगा अंतिम संस्कार।

सुल्तानपुर। बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे जय भद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया।

नई दिल्ली से आज उनका शव जनपद सुल्तानपुर के लिए लाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि कल धनपतगंज के मायंग गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

# दूल्हा निकला मंद बुद्धि वाला, लड़की ने किया शादी से इन्कार

सुल्तानपुर– कोतवाली लंभुआ अंतर्गत दुबौली गांव में शादी के लिए आया दूल्हा निकला मंदबुद्धि, सुबह लड़की ने शादी से किया इनकार। दियरा क्षेत्र के खेमाजितपुर से आई थी बारात। दोनों पक्ष पहुंचे कोतवाली लंभुआ,सुलह समझौते का चल रहा प्रयास। लंभुआ कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी बोले,दोनों पक्षों के बीच कराई जा रही वार्ता। आपसी तालमेल से समाधान निकालने का चल रहा प्रयास।

# संविदा कर्मी को मुख्य अभियंता फैजाबाद मंडल ने किया संमानित

सुलतानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के इसौली पावर हाउस में तैनात संविदा कर्मी दु:खीराम को अनके उत्कृष्ट कार्य के लिए फैजाबाद मंडल के मुख्यअभियन्ता हरीश वंशल ने संमानित किया। ये विगत आठ वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। इस वर्ष वसूली में लगभग एक करोड़ रूपये से ज्यादा की वसूली की है।

# तीन फरवरी को होगा साइबर थ्रेट्स एंड न्यू चौलेंजेज फार इंश्योरेंस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ बीमा संस्थान द्वारा ष्साइबर थ्रेट्स एंड न्यू चौलेंजेज फार इंश्योरेंसष विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन होटल मैपिल लीफ, तुलसी टाकीज के पीछे, पारिवारिक न्यायालय के सामने, लखनऊ में दिनांक। 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से किया जा रहा है। इस अवसर पर बीमा एवं साइबर विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने प्रतिनिधि को भेज कर कार्यक्रम का कवरेज करवाने की कृपा करें।

# रेल कर्मचारी ने प्रस्तुत किया ईमानदारी का अनुकरणीय उदाहरण

## –एक महिला यात्री का मूल्यवान पर्स सही सलामत लौटाया।

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आज दिनांक 02 फरवरी 24 को उत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01 पर स्थित महिला प्रतीक्षालय में कार्यरत महिला कर्मी श्रीमती सुनीता ने लखनऊ आई हुई एक महिला यात्री का खोया हुआ पर्स सही सलामत अवस्था में उस महिला यात्री को वापस करके कर्तव्यपरायणता तथा ईमानदारी का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण के अनुसार आज प्रातः एक महिला यात्री, डॉ. रश्मि शर्मा, एनएचपीसी की स्वतंत्र निदेशक का ट्रेन संख्या 15120 से (धामपुर–लखनऊ,) लखनऊ स्टेशन पर आगमन हुआ। उक्त महिला यात्री स्टेशन पर महिला प्रतीक्षालय में गयीं एवं वहाँ से वापसी में अपना दस्तावेजों और सामानों से भरा एक मूल्यवान पर्स प्रतीक्षालय में ही भूलकर चली गयीं। यह पर्स ऑन ड्यूटी, प्रतीक्षालय अटेंडेंट, सुनीता को मिला और उन्होंने इस पर्स को सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा उक्त महिला यात्री के आने पर इस पर्स को सही सलामत अवस्था में उस यात्री को सौंप दिया इस महिला यात्री द्वारा अपने पर्स की जांच करने पर इसमें रखा सारा सामान सही सलामत होने की पुष्टि की गई तथा इस महिला यात्री द्वारा रेल कर्मचारी सुनीता की सराहना करते हुए रेल प्रशासन के प्रति कृतज्ञ आभार व्यक्त किया गया।

# बसंत पंचमी मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

## राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को न हो परेशानी – डीएम

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बसंत पंचमी मेला को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा जो सहायता केन्द्र बनाये जा रहे है उसका उपयोगी स्थल चयन कर स्थापित कर उसे मेले में संचालित कर स्थापित्व प्रदान करें।जिन सामाग्रियों की नियमित आवश्यकता हो उसे खरीद ली जाये,जिससे बार–बार खर्चा से बचा जा सकें। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में निर्माण सामाग्री इधर उधर न पड़ी हों, घाटों पर प्रकाश व्यवस्था अच्छी रहे, सभी सम्बंधित विभागों को निर्देश दिये।जिलाधिकारी ने कहा कि राम की पैड़ी के पेड़ों की छटाई सुन्दर ढंग से करें, इसके लिए उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया।उन्होंने रोडवेज अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में संचालित ई–बसों को राम पथ पर ही यात्रियों को बैठायें उतारे तथा अन्य मार्गो पर व्यवस्थित एवं योजनाबद्व तरीके से संचालन सुनिश्चित करें,जिससे जाम की समस्या न हो और यात्रियों को परिवहन की सुगम व्यवस्था भी उपलब्ध हों।इस मौके पर एडीआरएम ने बताया कि रेलवे से रोजाना लगभग 15 हजार लोगों की संभावना है,जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गयी है। वही जिलाधिकारी ने एआरएम रोडवेज को स्टेशनों से परिवहन की व्यवस्थित सुविधा कराने हेतु सभी 225 ई–बसों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।एडीआरएम रेलवे ने बताया कि श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ने की स्थिति से निपटने हेतु रिजर्व ट्रेनों की व्यवस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर आधे घंटे में उपलब्ध हो जायेगी।एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत प्रयाग पुलिस फायर ब्रिगेड जल पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। एसएसपी राज करन नय्यर ने बताया कि मेले के साथ–साथ अब श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के श्री रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अच्छे व्यवस्था देना हमारी जिम्मेदारी है। इसे पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाई जिससे श्रद्धालु इसे भी आगे सुखद अनुभव लेकर जाएं

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी। इसी तरह से आगे भी और भी बेहतर ढंग से सभी कार्यक्रमों मेलो को सकुशल संपन्न कारण सभी विभाग जो भी करें उससे स्थायित्व मिले और सौंदर्य बोध भी हो।नगर निगम जो भी होर्डिंग या पोस्टर लगाए उसे सुंदर और व्यवस्थित रूप से ही लगाने दे। नगर निगम से लगाए अस्थाई शौचालय एवं अन्य शौचालय को नियमानुसार व्यवस्थित रूप से क्रियाशील रखें। ड्यूटी पर लगे मजिस्ट्रेट अपने आसपास शौचालय को नियमित चेक करें, साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें विभिन्न पथोंध्मार्गों के फुटपाथ पर किसी भी स्थिति में कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सुनिश्चित करें। धर्म पथ पर में रोड फुटपाथ,मीडियन पर कोई दुकानध ठेला नहीं लगना चाहिए।मजिस्ट्रेट अपने–अपने पॉइंट्स को एक बार देख ले और अपने कर्तव्यों एवं व्यक्तित्वो का समयक निर्वहन करें।बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,एडीआरएम रेलवे,मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एडीएम सिटी, एसपी सिटी सहित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण, विद्युत, पर्यटन, वन, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, रोडवेज, जल निगम, पंचायती राज, डेयरी आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# मण्डल रेल प्रबंधक ने किया चारबाग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

## द्वितीय प्रवेश द्वार –सेकंड एंट्री के निर्माणाधीन प्रगति कार्य से हुए अवगत

## जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी,लखनऊ में भी आगमन हुआ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल के चारबाग रेलवे स्टेशन री डेवलपमेंट के अंतर्गत द्वितीय प्रवेश द्वार (सेकंड एंट्री) का कार्य निरंतरता से प्रगति पर है ए इस निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत प्रस्तावित यात्री सुविधाओं के निर्माण कार्य एवं संरचना संबंधी कार्यों की प्रगति से अवगत होने के लिए आज दिनांक 02 फरवरी 2024 को मण्डल रेल प्रबंधक, श्री एस.एम.शर्मा ने इंजीनियरिंग,विद्युत,वाणिज्य एवं RLDA के अधिकारियों के साथ कार्यस्थल पर पहुंचकर सभी कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं इस संबंध में अपने आवश्यक निर्देश पारित किए एवं सुझाव दिए ए उन्होंने इन समस्त कार्यों को निर्धारित समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पन्न करने की बात पर विशेष बल दिया ए इसके उपरांत मण्डल रेल प्रबंधक ने सभी अधिकारियों के साथ ट्रेन मैनेजर, लोको पॉयलेट, सहायक लोको पॉयलेट एवं ट्रेन टिकट चेकिंग स्टाफ हेतु निर्माणाधीन किए जाने वाले 326 शय्याओं (बेड) वाले इंटीग्रेटेड रनिंग रूमध्टी.टी.ई. रेस्ट हाउस की कार्य प्रगति को परखा।

इसके अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबंधक का जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ में भी आगमन हुआ एवं वहाँ पहुंचकर उन्होंने अकादमी के अधिकारियों के साथ दिनांक 12.02.24 से दिनांक 16.02.24 तक आयोजित होने वाली "आल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट" के संबंध में की जाने वाले बैठक में सम्मिलित होकर विभिन्न प्रकार की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं के विषय में विभिन्न बिंदुओं पर मंत्रणा तथा विचार विमर्श किया आज के इस निरीक्षण एवं बैठक में अपर मण्डल रेल प्रबंधक शिवेन्द्र शुक्ला सहित अन्य विभागों के शाखाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।